राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 98

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, सोमवार, 16 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

22 तक पहुंचा पंकज आडवाणी का विश्व खिताब का संग्रह

>> 14

सरोकार

पेशेंट पोर्टल के जरिए कोलंबिया से होगा गरीबों का इलाज

साहिबगंज : झारखंड के आइटी विशेषज्ञ देवेश मिश्र कोलंबिया में आइटी विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने पेशेंट पोर्टल नाम का एक मोबाइल एप तैयार किया। इस एप के जरिए कोलंबिया के डॉक्टर भारत में मरीजों को मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श दे सकते हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

नानक नगरी में देखिए गुरु जी का 99 शहरों का सफर

कपूरथला : सिख पंथ के लिए आस्था का केंद्र सुल्तानपुर लोधी एक और मामले में खास होने जा रहा है। यहां गोलाकार आकृति की चार मंजिल की इमारत बनाई जा रही है, जहां गुरुनानक देव के 99 शहरों के सफर का दर्शन किया जा सकेगा। (पेज-11)

इमरान को सता रहा भारत से हार का डर

हौसले पस्त ▶ परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाक पीएम बोले, जंग हुई तो हार जाएंगे

कहा, कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच है परमाणु युद्ध का खतरा

इस्लामाबाद, एजेंसियां : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर परमाणु युद्ध होने की आशंका एक बार फिर जताई है। हालांकि अब उन्हें हार का डर सताने लगा है। उन्होंने मान लिया है कि पाकिस्तान परंपरागत युद्ध में भारत से हार जाएगा।

अल जजीरा टीवी चैनल को रविवार को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी परमाणु युद्ध शुरू नहीं करेगा। खुद को युद्ध विरोधी बताते हुए दावा किया कि जंग के नतीजे घातक हो सकते हैं। बोले-वियतनाम, इराक को ही देख लीजिए युद्ध के कारण कहीं अधिक गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जानते हैं कि दो परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच परंपरागत युद्ध शुरू होता है तो वह परमाणु युद्ध पर आकर खत्म हो सकता है। मोदी सरकार से हैरान-परेशान पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान परंपरागत युद्ध में पड़ता है तो वह भारत से लड़ाई हार भी सकता है।

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। एएफपी

अगर एक देश के पास दो ही विकल्प हों-या तो हथियार डाल दे या आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ता रहे। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। जब एक परमाणु संपन्न देश अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसीलिए हमने संयुक्त राष्ट्र से संपर्क साधा है। इसीलिए हम हर अंतरराष्ट्रीय फोरम पर अपील कर रहे हैं कि वह अभी इस मामले में दखल दें। अन्यथा कश्मीर मामला भीषण विनाश का कारण बन सकता है। यह मामला भारतीय उपमहाद्वीप के परे चला जाएगा।

सीमा पर गोलाबारी को लेकर भारत ने पाक को चेताया

नई दिल्ली : दुनिया के सामने न्यूक्लियर ब्लैक मेल की प्रधानमंत्री इमरान खान की कोशिशों के बीच भारत ने पाकिस्तान को संघर्षविराम उल्लंघन और सीमा पार से हो रही घुसपैठ को लेकर आगाह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिना किसी कारण के हो रही सीमा पार की गोलाबारी पर भारत गंभीर है। (पेज-6)

मोदी सरकार पाक को आर्थिक रूप से तबाह करने के एजेंडे पर :

पाकिस्तानी पीएम ने दावा किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत से बातचीत के कई प्रयास किए, लेकिन मतभेद दूर नहीं हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अब पाकिस्तान को एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की काली सूची में डालने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान को एफएटीएफ की काली सूची में डाला गया तो फिर पाक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे। वह हमें आर्थिक रूप से तबाह करने पर लगे हुए हैं। तभी हमें अहसास हुआ कि यह सरकार (मोदी सरकार) पाकिस्तान को बर्बादी की ओर ढकेलने का एजेंडा लेकर आई है।

370 हटने के बाद भारत से बातचीत का सवाल ही नहीं उठता : उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत सरकार से बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इमरान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर को अवैध तरीके से मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मजबूत देशों अमेरिका, चीन और रूस आदि का सहारा लेना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण तक नियंत्रण रेखा मार्च टाला : इमरान खान ने भारत से लगी नियंत्रण रेखा तक होने वाला मार्च फिलहाल टाल दिया है। वह 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने वाले अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दा उठाएंगे। इसलिए इमरान ने कुछ पाकिस्तानी राजनीतिक दलों और धार्मिक दलों से कहकर भारतीय सीमा तक पूर्व निर्धारित मार्च कुछ समय के लिए रोक दिया है। विगत शुक्रवार को इमरान ने कहा था कि ज्यादातर लोग एलओसी तक मार्च करके प्रदर्शन करना चाहते हैं।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तीन मंदिरों में तोड़फोड़

- ईश निंदा के आरोप में हिंदू स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआइआर दर्ज
- उपद्रवियों में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने वाले मौलवी मियां मिठू के समर्थक भी

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रविवार को तीन मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआइआर दर्ज किए जाने के बाद यह हंगामा हुआ है। मंदिरों के अलावा स्कूल और अल्पसंख्यक हिंदुओं की अन्य संपत्तियों में भी तोड़फोड की गई है। उपद्रवियों में सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने वाले मौलवी पीर अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू के समर्थक भी शामिल थे।

घोटकी जिले के सिंध पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक छात्र के पिता अब्दुल अजीज राजपूत ने ईश निंदा का मामला दर्ज कराया है। अजीज ने दावा किया कि प्रिंसिपल ने उसके सामने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। केस दर्ज होते ही भीड़ हिंसा पर उतर आई और एक हिंदू मंदिर और सिंध पब्लिक स्कूल में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। प्रिंसिपल के नहीं मिलने पर उपद्रवी और बेकाबू हो गए। मीरपुर मथेलो और अदिलपुर समेत घोटकी के आस-पास के इलाकों में भी उपद्रव हुआ। बाद में अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि आरोपित नोतन मल को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा कि घोटकी में हालात को तुरंत काबू कर लिया गया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता रमेश कुमार वंकवानी ने कहा कि मामले की जांच हैदराबाद के डिप्टी इंस्पेक्टर को सौंप दी गई है। वंकवानी पाकिस्तान हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं। वंकवानी ने भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने तीन मंदिरों, स्कूल और हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। उन्होंने पुलिस से दंगाइयों के खिलाफ केस दर्ज करने का अनुरोध भी किया।

इससे पहले, हिंसा भड़कने पर पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हिंसा का वीडियो साझा करते हुए सरकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। मानवाधिकार आयोग ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। मंदिरों और स्कूलों में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों के खिलाफ सुनवाई आज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के संबंध में विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वैधता को चुनौती और राज्य में लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के मामले भी शामिल हैं।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

आंध्र प्रदेश में नाव गोदावरी नदी में पलटी, 12 की मौत

अमरावती : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में नाव हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग लापता हैं। 60 सैलानियों और चालक दल के सदस्यों से भरी नाव गोदावरी नदी में पलट गई। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

हांगकांग में फिर चले आंसू गैस के गोले और पेट्रोल बम

रायटर : हांगकांग में रविवार को लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फिर टकराव हुआ। स्वायत्त क्षेत्र के विधानमंडल भवन और केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोका तो टकराव शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार छोड़ी तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और पेट्रोल बम चलाए।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 14

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी-20 मैच धुला

धर्मशाला : टी-20 विश्व कप 2020 की तैयारी को लेकर धर्मशाला में सीरीज का पहला मैच खेलने की भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों की उम्मीदों पर मौसम ने पानी फेर दिया। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को मोहाली में होगा। धर्मशाला में रविवार दोपहर करीब एक बजे पानी बरसना शुरू हुआ, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी छा गई।

उत्तर भारतीयों की योग्यता पर सवाल उठाने पर घिरे गंगवार

जागरण संवाददाता, बरेली

- केंद्रीय मंत्री ने कहा था, जो कंपनियां नौकरी देने आतीं हैं, उन्हें उनके मुताबिक युवा नहीं मिल पाते

उत्तर भारतीय युवाओं में कौशल की कमी की बात कहकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया कि मंत्री का यह बयान उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाला है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी बयान को शर्मनाक बताते हुए ट्वीट किया कि मंत्री माफी मांगें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बयान को युवाओं का मनोबल तोड़ने वाला बताया।

मोदी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर शनिवार को गंगवार ने बरेली में प्रेस वार्ता की थी। देश में मंदी और नौकरी न होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि नौकरियों की कमी नहीं है। उत्तर भारत में जो कंपनियां भर्ती के लिए आती हैं, उनमें से कुछ के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके काम के अनुसार गुणवत्ता नहीं मिल पाती। हम युवाओं को उस लायक बनाने पर काम कर रहे हैं। रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों की लंबी सूची के बाबत तर्क दिया कि बड़ी संख्या में पंजीकृत युवा अच्छी नौकरी हासिल कर चुके हैं। उससे भी बेहतर मौके पाने की तलाश में वे

संतोष गंगवार फाइल फोटो

अपना पंजीकरण निरस्त नहीं कराते। इसलिए सूची लंबी है।

प्रियंका बोलीं, ये नहीं चलेगा : कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि 'मंत्रीजी, पांच साल से ज्यादा समय से आपकी सरकार है। नौकरियां पैदा नहीं हुईं। जो नौकरियां थीं वो सरकार द्वारा लाई आर्थिक मंदी के चलते छिन रही हैं। नौजवान रास्ता देख रहे हैं कि सरकार कुछ अच्छा करे। आप उत्तर भारतीयों का अपमान करके बच निकलना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा।' जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि गंगवार के इस वक्तव्य से उत्तर भारत के युवाओं की परेशानी और बढ़ेगी। गंगवार जैसे वरिष्ठ नेता को इस तरह के वक्तव्य से परहेज करना चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्रियों के हास्यास्पद बयानों के बाद उत्तर भारतीयों की बेरोजगारी दूर करने के बजाय यह कहना कि रोजगार की कमी नहीं बल्कि योग्यता की कमी है, अति-शर्मनाक है।

रविवार को ऐसे दी सफाई

मैंने उत्तर भारतीयों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो मेरे सामने प्रमाण लाए। मैंने गुणवत्ता ठीक करने की बात की थी।

(ग्वालियर से दिल्ली लौटते वक्त फोन पर हुई बातचीत के अनुसार)

महंगा पड़ेगा खुले में कचरा जलाना, होगी जेल

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण ने दिए निर्देश, दिल्ली समेत चार राज्यों के मुख्य सचिवों से पूछी बैठक की तारीख

प्रतीकात्मक

> प्रदूषण से जंग में सख्ती बहुत जरूरी हो गई है। हालांकि नोएडा में पहले भी ऐसे कुछ मामलों में कार्रवाई की गई है, लेकिन अब समूचे दिल्ली-एनसीआर में सख्ती से कार्रवाई होगी। जल्द ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ सारी तैयारी पर बैठक भी की जाएगी।
>
> **-भूरेलाल, अध्यक्ष, ईपीसीए**

इस बार सर्दियों में खुले में कचरा जलाया तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने इसके लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, उनसे पूछा है कि सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी पर बैठक कब बुलाई जा सकती है।

वायु प्रदूषण के लिहाज से 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक का समय दिल्ली-एनसीआर में सर्वाधिक चिंताजनक होता है। हवाओं की दिशा उत्तर-पश्चिमी या पश्चिमी होने के कारण उसमें नमी की मात्रा काफी अधिक हो जाती है। ऐसे में प्रदूषक कण उड़ नहीं पाते और वातावरण में जमने लगते हैं। इस मौसम में अगर प्रदूषण बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जाए तो परिस्थितियां गैस चैंबर में बदलने लगती हैं। दिल्ली-एनसीआर ने 2016 और 2017 लगातार दो साल इस स्थिति का सामना किया है। 2018 में गैस चैंबर वाले हालात भले ही नहीं बने, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपातकालीन स्थिति अवश्य बन गई थी। इस साल समय रहते तैयारी शुरू कर दी गई है। सर्दियों में चोरी छिपे खुले में कचरा जलाने की घटनाएं खूब होती हैं। रात के अंधेरे में औद्योगिक कचरे, रबड़ और प्लास्टिक में आग लगाई जाती है। बीते वर्ष ईपीसीए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की टीमों ने ऐसे अनेक मामले पकड़े थे और पांच हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी ठोका था। इस बार ईपीसीए ने सख्ती जताते हुए ऐसा करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का निर्णय लिया है।

बताया जाता है कि ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने दिल्ली-एनसीआर में शामिल शहरों वाले चारों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्हें स्थानीय निकायों को इसके लिए निर्देश जारी करने को कहा गया है कि 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक की अवधि में दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू रहेगा। अगर कोई भी खुले में कचरा, रबड़ या प्लास्टिक जलाता हुए पाया जाए तो सार्वजनिक स्थल पर गड़बड़ी फैलाने या जनता के लिए परेशानी उत्पन्न करने के जुर्म में धारा 133 के तहत न केवल उस के खिलाफ मामला दर्ज हो बल्कि जेल की हवा भी खिलाई जाए। पत्र में कहा गया है कि सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए उनका क्या एक्शन प्लान है, इस पर ईपीसीए की टीम उन्हीं के गृहक्षेत्र में आकर बैठक करना चाहती है, तारीख तय करके इसकी सूचना दें।

गंगा की अविरल धारा में अब बाधा नहीं बनेंगे बांध

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

व्यवसायिक हितों के चलते ई-फ्लो के नियमानुसार गंगा में पानी न छोड़ने वाली मौजूदा हाइड्रोपावर परियोजनाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने मौजूदा हाइड्रोपावर परियोजनाओं को ई-फ्लो नियमों का पालन करने के लिए 8 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया था लेकिन अब इसे घटाकर 15 दिसंबर 2019 कर दिया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इसका मतलब यह है कि गंगा नदी पर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव तक गंगा नदी पर स्थित सिंचाई परियोजनाओं सहित सभी बांधों को 15 दिसंबर 2019 से ई-फ्लो के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सरकार ने यह कदम केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) की निगरानी और एक विशेषज्ञ दल की उस जांच रिपोर्ट के बाद उठाया है जिसमें कहा गया था कि कई मौजूदा जल विद्युत परियोजनाएं अपने व्यवसायिक हितों के चलते गंगा में जरूरी मात्रा में पानी नहीं छोड़ रही हैं। एक सितंबर 2019 को **दैनिक जागरण** ने यह खबर प्रकाशित करते हुए बताया था कि मौजूदा कंपनियां ई-फ्लो के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। सरकार ने 9 अक्टूबर 2018 को ई-फ्लो के नियमों की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत जिन परियोजनाओं में मानकों का पालन करते हुए जल छोड़ने की संरचना नहीं है, उन्हें तीन साल का समय दिया जाएगा ताकि वे संरचना में जरूरी बदलाव कर सकें।

ई-फ्लो की मौजूदा संरचना में बदलाव की जरूरत नहीं पेज>>7

अरैमको ने भारत में तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने का भरोसा दिलाया

रियाद : यमन के हाउती विद्रोहियों के ड्रोन हमले का शिकार हुई सऊदी अरब की तेल कंपनी अरैमको ने भारत में तेल आपूर्ति प्रभावित नहीं होने का भरोसा दिलाया है। सूत्रों के अनुसार, अरैमको ने एक भारतीय रिफाइनरी को बताया कि हमले के कारण तेल आपूर्ति पर तत्काल कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरैमको की अबकैक स्थित ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी और खुरैश स्थित बड़ी ऑयल फील्ड को शनिवार को ईरान समर्थित यमन के हाउती विद्रोहियों ने ड्रोन से निशाना बनाया था। (पेज-13)

श्रीनगर में दिखे 24 आतंकी, बड़ी वारदात की फिराक में

राज्य ब्यूरो, जम्मू

श्रीनगर में बड़ी वारदात की फिराक में 24 से अधिक आतंकी दाखिल हुए हैं। दहशतगर्द व्यापारियों को धमका रहे हैं कि दुकानें बंद रखें, वर्ना जान से मार देंगे। यही वजह है कि अभी तक बाजार पूरी तरह से नहीं खुले हैं। वहीं, आतंकियों की मौजूदगी की सूचनाओं से सुरक्षा एजेंसियों से लेकर राज्य प्रशासन तक सकते में है। ज्ञात हो, अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर के हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने पाबंदियों को लगभग हटा दिया है। वहीं, श्रीनगर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, श्रीनगर के डाउन टाउन में कुछ आतंकियों को घूमते देखा गया है। आतंकी लाल चौक, राजबाग, जवाहर नगर समेत कई क्षेत्रों में व्यापारियों को दुकानें न खोलने के लिए धमका रहे हैं। आतंकी वारदात करने के अलावा हालात खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

आतंकरोधी ऑपरेशन ढीले पड़े : एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पांच अगस्त के बाद आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन ढीले पड़े हैं। एक महीने से सिर्फ दो ही मुठभेड़ हुई हैं। इनमें एक 20 अगस्त को बारामुला और दूसरी नौ सितंबर को सोपोर में हुई है। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी नागरिक की हिंसा में मौत न हो। आतंकी वारदात के दौरान कई बार हिंसा होने की आशंका बनी रहती है। श्रीनगर शहर को साल 2012 में आतंकवाद मुक्त करार दे दिया था। शोपियां के आतंकवादग्रस्त क्षेत्र में बीते शनिवार को आतंकियों ने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप को जलाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी आतंकियों के होने की संभावना से इन्कार नहीं किया है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि आतंकी सरेआम घूम रहे हैं। वहीं, सूत्रों का कहना है कि दो दर्जन आतंकवादी श्रीनगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखे गए हैं।

मोदी का जलवा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कायम है, लोकप्रियता का आलम उन्हें मिले उपहारों की नीलामी को देखकर हो जाता है

500 रुपये के गमछे की 11 करोड़ की बोली

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

- प्रधानमंत्री को मिले 2772 उपहारों की ऑनलाइन नीलामी शुरू, नमामि गंगे के लिए निधि जुटाना है मकसद
- पीएसएलवी-सी7 के धातु से बने मॉडल की कीमत लगी एक करोड़
- कीमत तय करने में बरती गई पूरी पारदर्शिता, सीबीआइसी की ली गई मदद

अति महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के लिए निधि जुटाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले एक साल में मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी शनिवार को शुरू हुई। पीएम की लोकप्रियता का आलम यह है कि इन उपहारों के लिए लोग हैरान कर देने वाली बोली लगा रहे हैं। अंगवस्त्रम (गमछा या अंगोछा) की बोली 11 करोड़ रुपये लगी है तो पीएसएलवी-सी7 के धातु से बने मॉडल की कीमत एक करोड़ रुपये पहुंच गई। अंगवस्त्रम का मूल्य 500 रुपये और पीएसएलवी-सी7 की कीमत दो हजार रुपये रखी गई थी।

पहले कार्यकाल में मिले उपहारों की भी हुई थी नीलामी : इन उपहारों की नीलामी 3 अक्टूबर तक इंफारमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) की वेबसाइट https://pmmementos.gov.in/pmmementos/#/ पर की जाएगी। पीएम के तौर पर मोदी के पहले कार्यकाल में मिले उपहारों की नीलामी 27 जनवरी से 9 फरवरी 2019 तक चली थी। 4000 से अधिक उपहारों की नीलामी से मिला पूरा धन नमामि गंगे परियोजना को अर्पित किया गया था। तब सबसे अधिक बोली लकड़ी से बनी बाइक पर पांच लाख रुपये लगी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिले पीएसएलवी का मॉडल, इसकी एक करोड़ रुपये बोली लगाई गई है। जागरण

बोली लगाने से पहले देख भी सकते हैं स्मृति चिह्नों को : पिछली बार लोगों ने ऑनलाइन के साथ नीलामी स्थल इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) में जाकर बोली लगाई थी। मगर इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। एनजीएमए में जाकर इन स्मृति चिह्नों को देखा भी जा सकता है। रविवार को ही 100 से अधिक लोग इन्हें देखने पहुंचे। इस बार नीलामी के लिए कुल 2772 उपहार रखे गए हैं जो पीएम को देश में अलग-अलग स्थानों पर प्रवास के दौरान या दिल्ली में देश-विदेश के अतिथियों से मुलाकात में भेंट में मिले।

इस बार सबसे कम कीमत गणेश जी की छोटी सी मूर्ति की रखी गई है, जो 200 रुपये है। अधिकतम कीमत का उपहार 2.5 लाख रुपये का है। इनकी कीमत तय करने में पारदर्शिता का खयाल भी रखा गया है। इसमें कला विशेषज्ञों के साथ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) का सहयोग भी लिया गया है। नीलामी में गाय-बछड़े की धातु की प्रतिकृति की बोली 51 लाख रुपये लगी है। इसके साथ-साथ अंगवस्त्रम व पीएसएलवी-सी7 को बोली प्रक्रिया से हटा लिया गया है। नीलामी प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक फिलहाल बोलियों की जांच की जा रही है। अगर इन्हें संदिग्ध पाया गया तो इन उपहारों की नए सिरे से बोली लगेगी। नीलामी पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है।